

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।
 2. राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान / सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय समिति, देहरादून।
- शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) देहरादून: दिनांक: ०८ अप्रैल, 2011

विषय:-

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-12 (i)(c) के प्राविधानानुसार विशिष्ट श्रेणी तथा असहायता प्राप्त/निजी विद्यालयों में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या-3883/02-आर० टी०ई० (नियमावली)/2010-11, दिनांक 03.03.2011 के क्रम में, सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(i)(C) में निहित दिशा निर्देशों के क्रम में अधिनियम की धारा 2 (d) तथा 2(e) में परिभाषित/अधिसूचित अपवंचित समूह (Disadvantaged group) एवं कमजोर वर्ग (Weaker sections) के बच्चों को अधिनियम की धारा 2 (n) के उपखण्ड (iii) एवं (iv) में वर्णित विद्यालयों में प्रथम कक्षा अथवा यदि उससे पूर्व की कक्षा संचालित हो रही हो तो उस कक्षा के कुल सीटों की 25 प्रतिशत की सीमा तक के सीटों पर प्रवेश दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए इसके क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2011-12 के लिये निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित की जाती हैं:-

(1) विद्यालय हेतु पड़ोस (neighbourhood) की परिभाषा के अन्तर्गत वार्ड (स्थानीय निकाय अर्थात् ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो के वार्ड) को इकाई समझा जायेगा अर्थात् जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी वार्ड के उक्त श्रेणी के बच्चों को इसका लाभ अनुमत्य होगा। यदि उस वार्ड में उक्त श्रेणी के बच्चे प्रयोग्यता संख्या में उपलब्ध न हो तो उसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को होगा। शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना में यथा परिभाषित/अधिसूचित 2 (d) अपवंचित समूह (Disadvantaged group) तथा 2(e) कमजोर वर्ग (Weaker sections) हेतु सक्षम अथवा उप जिलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही उक्त प्रवेश अनुमत्य किया जायेगा।

(2) अप्रैल माह के प्रथम पक्ष में प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञाप्ति को सन्दर्भित करते हुए सार्वजनिक विज्ञाप्ति के माध्यम से समर्त विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों द्वारा निजी/असहायता प्राप्त विद्यालयों को उनकी कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षायें संचालित होने की दशा में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की

R-